कितना था और 30 सितम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार देश में चीनी का कितना भंडार था ; और

(घ) वर्ष 1993–94 (सितम्बर, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक) के दौरान चीनी की अनुमानत: कुल कितनी खपत हुई और सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के दौरान चीनी की कुल कितनी खपत का अनुमान लगाया गया है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित ग्रुप ने 1993–94 (अक्तूबर–सितम्बर) मौसम के दौरान 98.00 लाख टन की तुलना में 1994–95 के दौरान 118 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है।

(ग) 30 सितम्बर, 1993 और 1994 को देशी चीनी के स्टॉक क्रमश: 31.13 लाख टन और 18.33 लाख टन थे।

(घ) 1993–94 मौसम के दौरान चीनी की खपत 111.37 लाख टन थी और 1994–95 मौसम के दौरान अनुमानित खपत, पी०डी०एस० के लिए आयातित चीनी सहित लगभग 118 लाख टन होगी। उक्त आंकड़ों में ओ० जी० एल० के तहत प्राइवेट पार्टियों द्वारा आयातित चीनी शामिल नहीं है।

देश में गेहूं और चावल की कीमतें

5.18. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1994 के दैनिक "आब्जर्वर" में "हाई डोमेस्टिक प्राइजेज हिट व्हीट एक्सपोर्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं और चावल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अधिक हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो अगस्त से अक्तूबर, 1994 तक देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और चावल की कीमतें क्या-क्या थीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने खाद्यान्नों के प्रचुर भण्डार को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात का निर्णय लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो निर्यात के लिए कितनी मात्रा निर्धारित की गई है और भारतीय खाद्य निगम की गेहूं और चावल इकोनोमिक कीमतों में भी वृद्धि हुई है ; और

(च) यदि हां, तो वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 में इनकी कीमतें क्या थीं और वर्ष 1994–95 में कितनी कीमतें होने की सम्भावना है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मूल कृषि खाद्य पदार्थों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर केवल प्रधान बाजारों में ऊंचे व्यवधानों का ही दबाव नहीं है बल्कि इस पर विकसित देशों द्वारा मंजूर की गई निर्यात सब्सिडी का भी दबाव है। सब्सिडियों के बिना विश्व मूल्य मौजूदा मूल्यों से अधिक होंगे और भारतीय अनाज के निर्यात में निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करेंगे।

बासमती चावल के भारतीय निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय रूप में प्रतिस्पर्धी है और इनमें पिछले कुछ वर्षों से सतत वृद्धि हो रही है। तथापि, फिलहाल भारतीय गैर-बासमती उत्तम चावल और गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

अगस्त और अक्तूबर, 1994 में देश में और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और चावल की तुलनात्मक किस्मों के मूल्य

निम्नानुसार थे :—

(रुपये प्रति मीटरी टन में)

		घरेलू थोक मूल्य (औसत)	
		अगस्त, 1994	अक्तूबर, 1994
गेहूं	उत्तर	3861	3905
	पश्चिम	4950	4850
	पूर्व	4383	5233
	दक्षिण	6703	6862
चावल	उत्तर	6996	6994
	पश्चिम	7290	6849
	पूर्व	6386	6720
	दक्षिण	7375	7296

(अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन)

	अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य	
गेहूं (एच०आर०डब्ल्यू० 11% प्रोटीन अमरीका)	142–146	163–169
चावल (थाई टोटा 10%)	207–213	231–243

(घ) से (च) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) के स्टाक की अच्छी स्थिति की दृष्टि में सरकार ने 1994–95 के दौरान खुले बाजार से बिना न्यूनतम निर्यात मूल्य के गैर-डरूम गेहूं का निर्यात करने के लिए 5 लाख मीटरी टन की सीमा तक की मात्रा रिलीज की है और भारतीय खाद्य निगम को भी 5 लाख मीटरी टन की सीमा तक केन्द्रीय पूल से गैर-डरूम गेहूं निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम को शुरू में निर्यात के प्रयोजन से राज्य व्यापार निगम को खुले बाजार में बिक्री करने के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों पर 50,000 मीटरी टन तक गेहूं की बिक्री करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है । भारतीय खाद्य निगम ने अब तक गेहूं की किसी भी मात्रा का निर्यात नहीं किया है । केन्द्रीय पूल से चावल का निर्यात करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

विभिन्न वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम में इकानमिक मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये प्रति क्विंटल)

वर्ष	गेहूं	चावल
1991–92	390.79	497.04
1992–93	504.10	585.27
1993–94	532.03	665.10
1994–95 (अनुमानित)	562.45	724.00

Aid under World Food Programme

519. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will ihe Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whelher Government's attention has' been drawn to an 'editorial' publish' ed in "The Hindustan Times" dated 21st November, 1994 captioned "Food for the Poor" menionjng that India js to receive food aid worth about $ 9 million from the United Nations under World Food Programme (WFP) for a poverty alle-\iation programme in Gujarat when the Food Corporation of India is facing an acute problem of storing the ever-rising buffer stocks of foodgrains over 28 million tonnes as against the requirement of holding 16.6 million tonnes of foodgrains;